*324 *[The questioner (Shri Eaknath K. Thakur) was absent for answer vide page 28.*

*325 *[The questioner (Shri Amar Singh) was absent for answer vide page* 28./

*326 *[The questioner (Shri Isam Singh) was absent for answer vide page 29.]*

*327 *[The questioner (Dr. Allad} P. Raj Kumar) was absent for answer vide page* 297

रोजगार के अवसरो के सृजन का लक्ष्य

*328. **श्री राज मोहिन्दर सिंह** :†
श्री रवि शंकर प्रसाद :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों के सृजन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया हैं,

(ख) यदि हां, तो रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए वार्षिक लक्ष्य क्या हैं, और

(ग) दसवी योजना के अन्त तक विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्र-वार रोजगार के कितने अवसर सृजित किए जाएंगे?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया हैं।

विवरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) और मजदूरी रोजगार के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) नामक दो प्रमुख रोजगार योजनाएं कार्यान्वित करता हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, दसवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना के तहत भी रोजगार सृजित करने के लिए कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, वर्ष 2001-02 में एस.जी.आर.वाई. योजना को शुरू करते समय यह परिकल्पना की गई थी कि कुल मिलाकर

†सभा में यह प्रश्न श्री राज मोहिन्दर सिंह द्वारा पूछा गया।

प्रति वर्ष 100 करोड़ श्रमदिवस सृजित किए जाएगें। यद्यपि एस.जी.एस.वाई. और एस. जी.आर.वाई. ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार सृजित करने वाली योजनाएं हैं, तथापि इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) और वाटरशेड विकास कार्यक्रम, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) भी ग्रामीण क्षेत्रों में सीधें रोजगार सृजित करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अतिरिक्त रोजगार भी सृजत किए जाते हैं।

(2) यदि कार्यान्वयन की वर्तमान प्रवृत्ति को जारी रखा जाता हैं, तो एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत लगभग 425 करोड़ श्रमदिवस सृजित किए जा सकेंगे और दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के तहत आय सर्जक क्रिया-कलाप शुरू करने के लिए 45 लाख परिवारों को सहायता दी जा सकेगी।

Target for generating employment opportunities

†*328. SHRI RAJ MOHINDER SINGH:ft
SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have set any target to generate new opportunities of employment in the rural areas during Tenth Five Year Plan;

(b) if so, the annual target for generating employment opportunities; and

(c) the number of employment opportunities that would be generated by the end of the Tenth Plan in different sectors, sector-wise?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Ministry of Rural Development implements two major employment Schemes namely Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana for self-employment and Sampoorana Gameen Rozgar Yojana (SGRY) for wage-employment in rural areas of the country. Under these Schemes, no physical target to generate employment during the Tenth Five Year Plan and also annual plan has been fixed. However, while launching the SGRY Scheme

†Original notice of the question was received in Hindi.
†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raj Mohinder Singh.

in 2001-02, it was envisaged that overall 100 crore mandays would be generated every year. Although SGSY and SGRY are the employment generating schemes for the rural poor, the Indira Awaas Yojana (IAY) and the Watershed Development Programmes (Integrated Wastelands Development Programme (IWDP), Drought Prone Areas Programme (DPAP) and Desert Development Programme (DDP) also create employment indirectly in the rural areas. Additional employment is also generated under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY).

2. If the present trend of implementation is maintained, around 425 crore mandays would be generated under the SGRY and about 45 lakh families would be assisted take up income generating activities under different sectors under the SGSY during the Tenth Five Year Plan period.

श्री राज मोहिन्दर सिंह : चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब आप स्टेटवाइज सर्वेक्षण तो करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्लान में पढ़े-लिखे बच्चों और नौजवानों के लिए जो फिजीकल लेबर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वे पढ़े-लिखे बच्चों और नौजवानों के लिए जो फिजीकल लेबर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वे पढ़े-लिखे हैं, उनको मेंटल लेबर करने के लिए क्या इंतजाम किये हैं। इन्होने जो जवाब दिया हैं उसमें इन्होने डेली वेजिज का प्रोग्राम दिया हैं। मैं चाहूंगा कि जो टैंथ प्लस टू तक पढ़े लिखे बच्चे हैं, हिन्दुस्तान में करोड़ो ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए रोजगार का कोई पक्का इंतजाम किया जाये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, बेराजगारी देश के लिए एक प्रमुख समस्या हैं। महोदय, खासकर के जो गांव में बेरोजगारी हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनके लिए सरकार ने योजना बनाई हैं। चंकि सभी को नौकरी नहीं दी जा सकती हैं, इसकलिए उन्हें वेज एंड एम्पलायमेंट, कोई काम देकर उनको रोजगार दिया जाये, नम्बर दो, उनको प्रशिक्षण, उनको बैंको से ऋण और कुछ सबसिडी देकर के, उनको स्वरोजगार करने का प्रशिक्षण दिया जाये। महोदय, स्वरोजगार योजना चलाई जा रही हैं, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के लोग, खासकर के महिलाएं और अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग प्रशिक्षण लेकर स्थानीय चीजों का उत्पादन करें। सरकार उनके उत्पादनों को बाजार में भिजवाने का प्रबंध करती हैं जिससे लोग स्वरोजगार के जरिये रोजगार प्राप्त कर सकें। ...(व्यवधान)...क सम्पूर्ण रोजगार योजना चलाई जा रही हैं जिसमें 80 करोड़ मैंनडेज सृजन किया जाता हैं, जिससे गांव के बेरोजगार लोगों को काम के जरिये रोजगार मिल सके। अभी हाल में सरकार ने फैसला लिया हैं कि काम के लिए भोजन योजना को मजबूती से लागू किया जाये जिससे गांव के लोग काम करके अनाज हासिल कर सकें और उनको रोजगार मिल सकें।

श्री राज मोहिन्दर सिंह : चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से पूदना चाहूंगा कि हर प्रदेश में कोई नई कोटेज इंडस्ट्री इंट्रोड्यूज की गई हैं। मैं पूछना चाहूगा कि इन्होंने उस प्लान में क्या पंजाब और हरियाणा में कोई नयी कोटेज इंडस्ट्री लगाने का इंतजाम किया हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, यदि यह उद्योग और छोटे उद्योग का सवाल हैं तो यह उद्योग विभाग से होगा, लेकिन हमारा संबंध जो अनेक तरह की छोटी-छोटी योजनाएं गांवों में चल रही हैं, उनसे हैं। जो पहले से दस्तकारी लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करने का हैं। उनको प्रशिक्षण दिया जाये, उनको सामान उपलब्ध कराकर, उनको स्वरोजगारी सैल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उन्हे सहायता दी जाये। महोदय, इसमें दो तरह से रोजगार देने का प्रबंध हैं, लेकिन उद्योग हमारे विभाग से संबंधित नहीं हैं।हमारा तो संबंध विकास से हैं, गांव का कैसे विकास हो, वहां के लोगों की बेरोजगारी कैसे दूर हो, उसका इंतजाम हैं।

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Whenever we ask about the achievement of targets with regard to employment generation programmes, we receive a reply about the total list of programmes. As far as evaluation is concerned, with regard to IRDP, the achievement was only 14.8 per cent at that time. If we go through the achievements of the last three years of the current Plan, the target was that 30 per cent of the BPL families had to be covered while the achievement was only 4.5 per cent. So, we are not achieving the targets. The reason for not achieving the targets is that all these programmes are Central Government programmes, but we are not taking into account how these programmes will actually be implemented at the village level. Naturally, for the success of these programmes, you have to incorporate, in these, the traditional industries of the States. Different States have different traditional industries. So, would you incorporate the traditional industries with the employment generation programmes with a view to provide more employment to the youths? You have to do this. Are you thinking of replacing the existing programmes, according to the needs of the States, linking them with the traditional industries of the States?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :महोदय माननीय, सदस्य बेरोजगारी हटाने के लिए ट्रेडीशनल इण्डस्ट्री की बात कर रहे हैं। उनके सुझाव का हम स्वागत करते हैं और वह किया जाएगा। लेकिन महोदय, असल में हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहा गया हैं कि देश के प्रत्येक गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल में 100 दिन के रोजगार की गांरटी की जाएगी।

श्री सभापति : आपने बहुत अच्छा जवाब दिया हैं इनको ।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय कई एम्प्लोयमेंट गांरटी स्कीम्ज बनाई जा रही हैं, जिससे देश भर में प्रत्येक गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल भर में 100 दिनों के रोजगार की गांरटी की जाए और छोटे-छोटे व ट्रेडीशनल इण्डस्ट्री लगें, उसका हम स्वागत करते हैं। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करते हैं।welcome your proposal.

SHRI P.G NARAYANAN: Mr. Chairman, Sir, Tamil Nadu produces one lakh engineers and lakhs of graduates every year. We have to provide employment to them. Taking into account the high incidence of unemployment, especially among the educated youths, will the Government consider stepping up the assistance to Tamil Nadu for implementing employment generation programmes?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, बेराजगरी देश भर के तमाम राज्यों में हैं। राज्य सरकारें जितनी चेष्टा करेंगी उनको हम लोग उतनी सहायता करेंगे। खास करके तमिलनाडु ही नहीं, महोदय, अन्य राज्य भी ...(व्यवधान)..

श्री सभापति : जो उन्होने कहा हैं उसका जवाब दे दीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : वहीं तो मैं उत्तर दे रहा हू। वे तो ग्रेज्यूएट वाला सवाल पूछ रहे हैं। हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं और गांव के जो बेरोजगार लोग हैं, उनमें ग्रेज्यूएट भी है और वे गरीबी रेखा से नीचे हैं और लगता हैं और रूरल अन-एम्प्लोइड हैं। अगर गांव में वे बेरोजगार हैं तो उनके लिए हम प्रबंध करें।

Inclusion of 'TULU' language in the Eighth Schedule of the Constitution

*329. Dr. VIJAY MALLYA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is a proposal before Government to include Tulu' language in the Eighth Schedule of the Constitution; and

(b) by when a decision in the matter is expected?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.